EDITORIAL

Let the Tasks guide us

The telecom trade union movement is in its historical junction to settle the pressing demands like wage revision by relaxing or fighting out the affordability condition of DPE, bringing back the importance of PSUs in the Digital Communication Policy and safeguarding its infrastructure from the policy attacks of unbundling, retaining tower business, fighting some dangerous decisions of CMDs meet of all PSUs in April 2018 in the presence of Prime Minister Shri Narendra Modiji. Unless we understand the issues, it is difficult to advance our causes.

After our struggle and talks with the minister MOC and Secretary Telecom the issue of taking up our case to the cabinet for relaxation of affordability and permitting wage revision is drawing the serious attention of the concerned wings and divisions of DOT. DPE has given its clarification to DOT thro its letter dated April 18th though BSNL does not fall under the category of para 5 affordability clause based on Committee of Secretaries recommendations and DoT can examine the issue at its end to take up the case to the cabinet for relaxation. It was reported that in that Committee the cabinet secretary had given his opinion that minor relaxation is possible but no major deviation. But nobody knows what major deviation is and what all the minor relaxations are. Let us hope the relaxation we seek for BSNL comes under minor relaxation.

Earlier DPE has replied thro its letter dated January 31st in the same lines to NFTE also for its request of relaxation in the 8th round guidelines for Non- Executives. MTNL unions though they got 73.8 fitment that also from Jan. 2018 instead of 78.2 that we got from June 2013 are also claiming that their case of wage revision would also be addressed by DOT jointly together with BSNL.

The Executive wage revision helped last time in 2007 on three aspects. One is wage revision for them, second is equivalent fitment benefit for Non- executives and the third one is Pension revision on the same formula. This time also we are demanding the same 15 % fitment formula and we should jointly purse that with executive Unions. For the Non- Executives DOT has endorsed the 8th round guidelines so belatedly thro its letter dated April 27th and advised BSNL to take steps with strict compliance with the DPE instructions of Nov. 24th 2017. BSNL should constitute a joint bilateral wage negotiation committee (BWNC) like in other PSUs notifying the names of both official and staff side. The chairman should be either CMD himself as that of in the other PSUs, if not at least Director (HR) who is leading the National councils.

The prime task in the committee is wiping out the present stagnation of 25000 employees and constructing scales in such a way to avoid any future stagnation for thousands of employees. This is possible if we all do some home work. The pension contribution issue should be tackled when the question of deciding better spans. If management is reluctant to accommodate non recognized union representatives, then staff side may consider forming their internal committee to arrive at consensus with the non recognized unions also.

BSNL has already placed its demands to the policy framers that the importance of PSUs should be recognized in the Digital Communication policy. Unfortunately the draft failed to appreciate the PSUs role. BSNL should be compensated for its role of achieving the NTP 2011 regarding BB expansion. The present policy is silent about the same. The demand of BSNL to handover the Smart cities project to BSNL should also be accepted. Government agencies should be advised to use and utilize BSNL and other Telecom PSU services only. The project of taking digitalization to the underprivileged section of the people should also be handed over to BSNL to have better monitoring system by the Govt. The expertise in the PSUs should be encouraged to widen their PSU markets. The provision of 4G / 5G as capital infusion is must for the growth of BSNL.

The meet of Vision 2022 on 9th April participated by all the CMDs in the presence of our Prime Minister has taken a lot of decisions to redefine the role of PSUs and the PSUs are instructed to give their feedback within three months for the implementation. Six sectors including Telecom were identified as loss making sectors. Exit of Government from the non priority sector is one important decision. BSNL falls under priority sector as per 14th Finance Commission. The Government is constituted 15th Finance Commission and its report is expected by the end of 2019. We hope that commission should place us in the Higher Priority sector as the telecom infra is placed equivalent to railways, roadways and airways. The vision 2022 is for outsourcing and sending employees on sabbatical leave. The serious view of FR 56 J is advocated in the vision statement. There need not be any socialization on the issue of promotion and star performers should be honoured and separate fast track promotion scheme should be drawn are some of the other recommendations. We hope that the PSU unions will study the Vision 2022 decisions and evolve appropriate strategy to face the onslaughts.

The tower corporation issue is presently at the arena of Judiciary. Let us hope for the favourable judgment. Trimming our organization is the task before us in the circle secretary meeting at Delhi. Let us understand the tasks and advance the cause of BSNL and the workers.

संपादकीय

कार्य ही मार्गदर्शन करेंगे

दूरसंचार क्षेत्र में संचालित श्रमिक संगठनों का आंदोलन एक ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ा है जहां उसे वेतन संशोधन के कठोर दबाव को झेलते हुए सक्षमता का कठिन प्रतिबंध जो डीपीई के द्वारा प्रतिपादित है में छूट दिलाते हुए अथवा लड़कर संकट से उभरना है, साथ ही निगम के प्रतिष्ठा को वापस लाकर डिजीटल संचार के क्षेत्र में अग्रणी भूमिका निभानी है तथा अपने टावरों को सुरक्षित रखने की जवाबदारी सहित अनबंडलिंग की नीतिगत आक्रमण सहित अप्रैल 2018 में सभी लोक उपक्रमों के सीएमडी की बैठक में लिए गये खतरनाक निर्णय जो श्री नरेन्द्र मोदी जी की उपस्थिति में लिये गये थे से रूबरू होते हुए अपने संसाधनों की सुरक्षा एवं कर्मचारियों की हित रक्षा एक चुनौती बन गई है।

हम जब तक विषय बिंदु की समझदारी नहीं रखेंगे हमें अपने कार्य को अग्रसर करना कठिन होगा।

हमारे आंदोलन के परिपेक्ष्य में माननीय संचार मंत्री एवं सचिव दूरसंचार विभाग से वार्ता संभव हुई। जहां माननीय मंत्री महोदय जी ने स्पष्ट आश्वासन दिया किएफाडिबिलिटी की कंडीशन को मंत्री परिषद द्वारा शिथिल कराकर वेतन संशोधन की कार्यवाही आगे बढ़ायी जायेगी। इस परिपेक्ष में बात आगे भी बढ़ी है। लोक उपक्रम विभाग ने अपने 8 अप्रैल 2018 के पत्र के माध्यम से यह स्पष्ट कर दिया है कि डीपीई गाइडलाइन जो सचिवों की समिति ने अनुमोदित की तथा मंत्री परिषद से अनुमोदित है उसके अनुसार बीएसाएनएल एफाडिबिलिटी क्लॉज के पैरा 5 में नहीं आता है। अतः इसमें छूट के लिए डीओटी के द्वारा मंत्रिपरिषद से छूट लेकर ही आगे बढ़ने का रास्ता मिल सकता है। ऐसी सूचना है कि सचिव समिति की बैठक में कैबिनेट सचिव ने कहा हे कि छोटी छूट की व्यवस्था की जा सकती है परंतु कोई बड़ा परिवर्तन संभव नहीं है। हमें पता नही है कि छोटी छूट और बड़े परिवर्तन में क्या शामिल है। हमें आशा करनी है कि बीएसएनएल के लिए अफाडिबिलिटी कंडीशन में छूट एक छोटी छूट के दर्जे में आयेगी।

पूर्व में एनएफटीई द्वारा प्रधानमंत्री को लिखे गये पत्र का प्रतिउत्तर देते हुए– डीपीई ने इसी लाइन पर एनएफटीई को जवाब दिया था। एमटीएनएल के साथी जिन्हें 78.2 प्रतिशत की जगह 73.8 प्रतिशत फिटमेंट मिला वह भी जनवरी 2018 से जबकि बीएसएनएल के साथी 78.2 प्रतिशत फिटमेंट जून 2013 से ही प्राप्त कर चुके हैं। एमटीएनएल के साथी भी दबाव बना रहे हैं कि डीओटी उनके वेतन संशोधन का मुद्दा भी बीएसएनएल के साथ संयुक्त रूप से मंत्री परिषद को सुपुर्द करें।

गत वेतन संशोधन 2007 के समय एक्जीक्युटिव संवर्ग के लिए निर्धारित मापदंड ने तीन तरह से हमें सहयोग किया। पहला उनका वेतन संशोधन दूसरा नॉन–एक्जीक्युटिव के लिए समान फिटमेंट लाभ एवं तृतीय समान फार्मूले पर पेंशन संशोधन। इस बार भी हम समान राय से 15 प्रतिशत फिटमेंट की मांग कर रहे हैं। बहुत देर से डीओटी ने 27 अप्रैल 2018 के पत्र द्वारा नान–एक्जीक्युटिव कर्मचारियों के लिए आठवे दौर की वार्ता हेतु कमेटी बनाने की अनुमति दे दी है। बीएसएनएल को अधिकारियों एवं कर्मचारी पक्ष की समिति बनाकर द्विपक्षीय वार्ता शुरू करनी चाहिए परंतु इस संयुक्त द्विपक्षीय समिति का अध्यक्ष सीएमडी अथवा निदेशक (कार्मिक) स्तर के उच्च शक्ति प्राप्त अधिकारी होने चाहिए।

हमारी प्राथमिकता 25000 कर्मचारियों के स्टैगनेशन को समाप्त करने की दिशा में प्रयास एवं एक ऐसे वेतनमान का निर्धारण जिससे हजारों कर्मचारी स्टैगनेशन के चपेट में ना आ जाये ये देखना है। यह तभी संभव है जब हम कुछ गृह कार्य भी करें। पेंशन अनुदान के संबंध में भी ध्यान रखना होगा जब हम अच्छे वेतनमान की बात करेंगे। अगर प्रबंधन सभी नान–एक्जीक्युटिव यूनियन की भागीदारी स्वीकार नहीं करते तो हम एक आंतरिक समिति बनाकर सबकी सहमति ले सकते हैं।

बीएसएनएल ने नीति बनाने वालों के समक्ष अपनी लोक उपक्रम को डिजीटल कम्युनिकेशन के लिए महत्वपूर्ण स्थान देने की मांग रखी है। दुर्भाग्यवश मसौदे में इस प्रकार की व्यवस्था नहीं है। बीएसएनएल को 2011 के राष्ट्रीय दूरसंचार नीति की ब्राड–बैंड की फैलाव पूरी करने के लिए क्षतिपूर्ति देनी चाहिए। स्मार्ट सिटी परियोजना को भी

बीएसएनएल के सुपुर्द होना चाहिए। सरकारी ईकाइयों को बीएसएनएल की सेवा का उपयोग करने की पाबंदी देनी चाहिए। सक्षम समुदाय को डिजीटलाइजेशन के समृद्ध जुड़ाव की परियोजना भी बीएसएनएल के सुपुर्द करनी चाहिए ताकि सरकार पूर्ण निगरानी रख सके। स्पेक्ट्रम 4जी/5जी बीएसएनएल को उपलब्ध करानी चाहिए।

9 अप्रैल को विजन 2022 के लिए आहुत बैठक में सभी लोक उपक्रमों के सीएमडी ने भाग लिया, बैठक में माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी भी उपस्थित थे। लोक उपक्रमों को परिभाषित करने के लिए कई निर्णय लिये गये और इसके कार्यान्वयन के लिए लोक उपक्रमों को तीन माह के अंदर प्रतिक्रिया देने का निर्देश दिया गया है। दूरसंचार समेत छः क्षेत्रों को हानि जनित क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। गैर प्राथमिकता वाले क्षेत्र से बाहर निकलना एक महत्वपूर्ण निर्णय है।

चौदहवें वित्त आयोग के अनुशंसा के अनुसार बीएसएनएल प्राथमिकता के क्षेत्र में आता है। सरकार ने पन्द्रहवें वित्त आयोग का गठन किया है और इसका अनुशंसा 2019 के अंत तक आने की संभावना है। हमें आशा है कि आयोग बीएसएनएल को उच्च प्राथमिकता वाले क्षेत्र में रखेगी क्योंकि दूरसंचार इन्फ्रा, रेलवे, सड़क मार्ग, और वायु मार्ग की श्रेणी में ही है। विजन 2022 आउटसोर्सिंग एवं कर्मचारियों को विश्राम अवकाश पर भेजने की बात करती है। एफआर 56जे के गंभीर प्रावधानों की वकालत की गई है। पदोन्नति के मुद्दे को समाजीकरण से दूर रखने स्टार परफारमेंस को सम्मानित करने तथा फास्ट ट्रैक पदोन्नति को अलग करने के अतिरिक्त कुछ और अनुशंसाएं हैं। हमें आशा है कि श्रमिक संघ विजन 2022 के प्रावधानों और सिफारिशों का अध्ययन करेंगे तथा इसके कुपरिणामों से बचने के लिए रणनीति तैयार करेंगे।

टावर कंपनी का मुद्दा न्यायपालिका के शरण में है। हमें अनुकूल निर्णय की आशा करते हैं। संगठन को सुसज्जित करना हमारा पहला दायित्व है जिसे दिल्ली में आहूत परिमंडलीय सचिवों की बैठक में करनी चाहिए। आइये, हम दायित्व को समझे और बीएसएनएल तथा कर्मियों के मकसद को आगे बढ़ाएं।